

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

छेदन उराँव

बनाम

मो० साबिर हुसैन वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 41/2010-11

वाद का प्रकार :- म्यूटेशन अपील (Mutation Appeal)

आवेदक श्री छेदन उराँव पिता-लगनु उराँव ग्राम-कुदरा थाना-सिसई जिला-गुमला ने भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं०-07/2010 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं०-145 प्लॉट नं०-891 रकबा-0.87 एकड़ मौजा कुदरा थाना-सिसई जिला-गुमला में अवस्थित है जो अपीलार्थी की बकास्त भूईहरी प्रकृति की जमीन है। जिसका हस्तांतरण धारा-48 सी० एन०टी० एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अवैध है। प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज हेतु साबिर हुसैन अंचल अधिकारी सिसई के समक्ष दाखिल किया गया, जिसे पूर्ण सुनवाई के पश्चात खरिज कर दिया गया।

उत्तरवादी साबिर हुसैन द्वारा दावा प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत भूमि को उन्होंने रजिस्ट्री पट्टा सं०-2156 दिनांक-28.08.2009 के माध्यम से बिक्रेता बालेश्वर साहु पिता-बालमुकुन्द साहु से कय किया गया है। उत्तरवादी का अभिकथन है कि विवादित भूमि को बालेश्वर साहु एस०ए०आर० वाद सं०-597/1976-77 के माध्यम से दिनांक-29.11.1976 व 10.12.1976 से प्राप्त किया था।

दाखिल खारिज वाद के लिए क्रेतागण का प्रश्नगत जमीन में विधिक दखल अनिवार्य है बगैर विधिक दखल के दाखिल खारिज अवैध है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि (For valid mutation it is necessary for the application to prove law full possession over the lands in ancestation and law full possession only recognized through valid transaction relied on J.B.C.J 2016 S.C.135)

अपीलार्थी का कथन है कि सन् 1940 में बालेश्वर साहु का जन्म नहीं हुआ था। वर्ष 2008 के भोटर लिस्ट में बालेश्वर साहु का उम्र 53 वर्ष दर्ज है जिससे यह प्रमाणित होता है कि बालेश्वर साहु का जन्म 1956 ई में हुआ था ऐसी परिस्थिति में बालेश्वर साहु का यह दावा कि सन 1940 ई० में उसके द्वारा प्रश्नगत जमीन को खतियानी रैयत के पुत्र से खरीदा गया था सिर्फ काल्पनिक है तथा एस०ए०आर० कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने की नियत से 1940 के हस्तांतरण का किस्सा गढ़ा गया। इस परिपेक्ष्य में बालेश्वर साहु एस०ए०आर० कोर्ट में 1940 के हस्तांतरण के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए और न ही इस वाद में भी उत्तरवादी तथाकथित 1940 का कागजात प्रस्तुत किए। वैसे भी धारा 46 सी०एन०टी० एक्ट के मुताबिक गैर-आदिवासी को बकास्त भूईहरी मुण्डई जमीन का हस्तांतरण संभव नहीं है।

यह स्पष्ट है कि सन 1975-76 में बकास्त भूईहरी मुण्डई जमीन में एस०ए०आर० कानून लागू नहीं था, सन् 1975-76 में प्रश्नगत जमीन के संबंध में वगैर प्रावधान के एस०ए०आर० केश रजिस्टर्ड होना तथा वगैर प्रावधान के एस०ए०आर० केश प्रश्नगत जमीन में चलाना तथा उसमें आदेश पारित कर बकास्त भूईहरी- मुण्डई जमीन को गैर- आदिवासी के नाम हस्तांतरण का अवैध

नामा पहनाना विधि विरुद्ध है तथा Fraud against statute भी है। इस संबंध में 2003(3) JLJR730 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि Fraud against statute can not be recognized as valid one in this case Honourable court have not recognized oral transfer made in 1951 in between tribble and non tribble

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी ने न्यायालय से धोखाधड़ी करते हुए सन-1940 के मनगढंत तथ्य को प्रस्तुत किया जिस समय बिकता-क्रेता दोनों का जन्म नहीं हुआ तथा वैसे हस्तांतरण को न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 केश नं0-597/1976-77 को आदेश दिनांक-10.12.1976 से रिभैलिडेट किया गया। चूंकि सन 1940 में कोई हस्तांतरण हुआ नहीं था ऐसी परिस्थिति में उक्त हस्तांतरण का एस0ए0आर0 कानून के विरुद्ध एस0ए0आर0 वाद लागू कर वैध हस्तांतरण को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है, तथा वैसे कार्य न्यायालय के साथ वो कानून के साथ धोखाधड़ी की संज्ञा में आती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में 1994(1) SCC1 में यह अवधारित दिया कि Judgment or decree Obtained by fraud to be treated as nullity and can be questioned even in collateral proceeding fraud Meaning of Non-disclosure of relevant and material documents with a view to obtain advantage amounts to fraud-partition suit filed by respondent without disclosing deed of release executed by him relinquishing his rights in the property and preliminary decree obtained-Held decree obtained by non-disclosure of the release deed amounted to fraud on Court and hence decree liable to set -aside.

इस वाद में भी बालेश्वर साहु द्वारा 1940 के हस्तांतरण का मनगढंत तथ्य प्रस्तुत किए तथा 1940 के उक्त अवैध हस्तांतरण का कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए तथा एस0ए0आर0 कानून का सहारा लेकर जबकि बकास्त भूर्ईहरी मुण्डई जमीन एस0ए0आर0 कानून लागू नहीं होता है बावजूद इसकी एस0ए0आर0 कानून का सहारा लेकर सन 1940 के अवैध हस्तांतरण को वैध करा लिया जिसका अस्तित्व ही नहीं है। एस0ए0आर0 कोर्ट द्वारा एस0ए0आर0 केश नं0-597/1976-77 में पारित आदेश जो कि धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया उक्त आदेश को valid order की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता है तथा वैसे आदेश से बालेश्वर साहु को भी हक प्राप्त नहीं हो सकता इस संबंध में 2007(2) JLJR SC184 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है-

It is well settled principle of law that if any judgement or order is obtained by fraud it cannot be said to be judgement or order in law-such a judgement decree or order by the first court or by the final court has to be treated as nullity by every court superior or interior-it can be challenged in any court at any time in appeal revision writ or even in collateral proceeding no illegality in impugned order.

इस प्रकार अंचल अधिकारी सिसई द्वारा साबिर हुसैन के दाखिल खारिज को रद्द किया जाना बिलकुल सही निर्णय था। उनके द्वारा म्यूटेशन रिवीजन अपील वाद सं0-07/2010 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

है:-

- 1 दाखिल खारिज अपील वाद सं०-07/2010-11 की नकल की छाया प्रति।
- 2 खतियान खाता नं०-145 की नकल की छाया प्रति।
- 3 खेवट 11/3 की नकल की छाया प्रति।
- 4 निरंतर खतियान खाता नं०-145 की नकल की छाया प्रति।
- 5 बन्डा पर्चा की नकल की छाया प्रति।
- 6 एस०ए०आर० वाद सं०-597/1976-77 की मूल प्रति।
- 7 एस०ए०आर० वाद सं०-498/1975-76 की मूल प्रति।
- 8 रजिस्ट्री पट्टा सं०-2156 दिनांक-28.08.2009 की नकल की छाया प्रति।
- 9 भोटर लिस्ट विधान सभा सिसई 2008 भाग सं०-43 क्रम सं०-297 आयु 68 वर्ष बनेया उरॉव उर्फ वाने उरॉव पिता-सुखन उरॉव का की नकल की छाया प्रति।
- 10 भोटर लिस्ट विधान सभा सिसई 2008 भाग सं०-44 क्रम सं०-97 आयु 53 वर्ष बलेश्वर साहु पिता बालमुकुन्द साहु का नकल की छाया प्रति।
- 11 मृत्यु प्रमाण पत्र बनेया उरॉव उर्फ वाने उरॉव दिनांक-09.04.2009 की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है यह म्यूटेशन अपील वाद खाता सं०-145 प्लॉट सं०-891 रकबा-0.87 एकड़ जमीन जो ग्राम कुदरा थाना-सिसई जिला-गुमला में अवस्थित है का खतियान रिवीजन सर्वे में सुखन उरॉव व कोचा उरॉव के नाम से बकास्त भूईहरी दर्ज है। खतियानी रैयतों ने उपरोक्त जमीन को सन-1940 ई० में बालेश्वर साहु को बिक्री कर दिया था तथा दखल भी दे दिया था। तत्पश्चात् सन-1976-77 ई० में बनेया उरॉव वल्द सुखन उरॉव जो खतियानी रैयत का वारिश था, उसने एस०ए०आर० वाद सं०-597/1976-77 बालेश्वर साहु के विरुद्ध दायर किया। माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी ने दिनांक-29.11.1976 ई० को 300/ रुपया बनेया उरॉव को देने का आदेश दिया। आदेशानुसार बालेश्वर साहु ने दिनांक-10.12.1976 को क्षतिपूर्ति की राशि देकर जमीन के हस्तांतरण को वैध करा लिया। उक्त आदेश के विरुद्ध बनेया उरॉव या किसी अन्य के द्वारा कोई अपील या रिवीजन कभी दायर नहीं किया गया। इस तरह बालेश्वर साहु का हकीयत एवं दखल सम्पुष्ट कर दिया गया। उक्त आदेश के पश्चात् विद्वान अंचल अधिकारी सिसई ने नामांतरण वाद सं०-04/1979-80 दिनांक-28.05.1979 को नामांकन भी स्वीकृत कर दिया तथा वे 2008-09 तक सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे थे, जब बालेश्वर साहु को रुपये की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने खाता नं०-145 प्लॉट-891 रकबा-0.87 एकड़ जमीन को वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में निबंधित पट्टा सं०-2556 दिनांक-28.08.2009 को बिक्री कर दिया तथा दखल भी दे दिया। अभी उक्त जमीन पर अपीलार्थी का ही शांति पूर्ण दखल है। नामांतरण आवेदन वाद संख्या-230आर27/2009-10 अंचल अधिकारी सिसई के न्यायालय में दायर किया। अंचल अधिकारी, सिसई ने जाँच प्रतिवेदन की मांग की जाँचोपरांत स्थानीय राजस्व कर्मचारी ने अपीलार्थी का दखल पाते हुए सिर्फ अपने प्रतिवेदन में इतना ही लिखा कि खतियानी रैयत के वारिश आपत्ति कर रहें हैं, इसलिए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इस पर अंचल अधिकारी ने माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला से दिशा-निर्देश मांगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप स्वयं नामांतरण आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं चूँकि एक सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार बालेश्वर साहु के नाम से नामांतरण सन् 1979-80 ई० में ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी

अपीलार्थी का नामांतरण अस्वीकृत कर दिया। इन तथ्यों के अलावे अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय का एक नियमन भी भूईहरी जमीन के संबंध में दाखिल किया वह नियमन बी०एल०जे०आर 1992 पेज-986 में वर्णित है कि माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा है कि भूईहरी जमीन पर एस०ए०आर० वाद सन् 1986 ई० से लागू हुआ है और उसके पूर्व जिस तरह का भी हस्तांतरण है या बेदखली है, उसमें प्रतिकूल दखल के आधार पर दखलकार व्यक्ति का हक 12 साल में ही हो जाता था।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है:-

1. एस०ए०आर० वाद सं०-597/1976-77 का आदेश दिनांक-29.11.76 की छाया प्रति।
2. लगान रसीद की छाया प्रति।
3. निबंधित पट्टा:-2156/2009 की छाया प्रति।
4. किमिनल रिवीजन 09/2011 की छाया प्रति।
5. करेक्शन Slip की छाया प्रति।
6. टाईटल सूट 17/2014 की छाया प्रति।
7. राजस्व अपील की छाया प्रति।
8. बिजली कनेक्शन की छाया प्रति।

उभय पक्षों का लिखित बहस प्रस्तुत कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सुदूरवर्ती गांवों में आदिवासी जमीन को खुले में बिना कब्जे/घेराबंदी के छोड़ रखा जाता है। हाँलाकि, किसी प्रकार के निर्माण कार्य होने पर उनके संज्ञान में आता है, फिर उनके द्वारा न्यायिक पहल पर अपने अधिकार को दर्शाया जाता है। इस वाद में भी ऐसे निर्माण कार्य संज्ञान में आने के उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा Title Suit वाद, Sec.107 संबंधित वाद, SAR वाद, Deed Cancellation वाद वगैरह के माध्यम से लगातार कोशिश की गई जिसके बिन्दुओं को भी अवलोकन किया गया।

किसी भी प्रकार से उत्तरवादी का उक्त जमीन पर दखल-कब्जा नहीं दर्शाया जा सका। खतियानी रैयत के आधार पर आदिवासी जमीन को भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा बिना किसी आधार के हस्तांतरण कराई गई। साथ ही भूईहरी जमीन के संबंध में इस हस्तांतरण में भी वैद्य नहीं कहा जा सकता है।

अपील स्वीकृत की जाती है एवं जमीन को अपीलकर्ता के दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाता है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को प्राप्त कराई जाय, साथ ही निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

28.04.22
उपायुक्त,
गुमला

28.04.22
उपायुक्त,
गुमला